ध्येय IAS
most trusted since 2003

DAILY pre PARE
Current affairs summary for prelims

15 October 2024

ग्रामीण वित्तीय समावेशन पर नाबार्ड सर्वेक्षण

संदर्भ: हाल ही में नाबार्ड ने दूसरे अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण (2021-22) के निष्कर्ष प्रस्तुत किए। यह सर्वेक्षण 100,000 ग्रामीण परिवारों के डेटा पर आधारित है और कोविड-19 के बाद की अवधि में विभिन्न आर्थिक और वित्तीय संकेतकों का विश्लेषण करता है। पहले सर्वेक्षण का आयोजन कृषि वर्ष 2016-17 में किया गया था और नवीनतम परिणाम पिछले पाँच वर्षों में ग्रामीण आर्थिक स्थितियों के विकास के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं।

एनएएफआईएस 2021-22 के प्रमुख निष्कर्ष:

- **औसत मासिक आय में वृद्धि:** 2021-22 में औसत मासिक आय 57.6% की वृद्धि के साथ 8,059 से बढ़कर 12,698 हो गई। इस दौरान कृषि परिवारों की औसत आय 13,661 रही , जबकि गैर-कृषि परिवारों की औसत आय 11,438 रही।
- **औसत मासिक व्यय में वृद्धि:** इस अवधि में औसत मासिक व्यय 6,646 से बढ़कर 11,262 हो गया है। कृषक परिवारों ने औसतन 11,710 और गैर-कृषि परिवारों ने 10,675 का खर्च किया।
- **वित्तीय बचत में वृद्धि:** वार्षिक औसत वित्तीय बचत 9,104 से बढ़कर 13,209 हो गई। बचत की रिपोर्ट करने वाले परिवारों का प्रतिशत 50.6% से बढ़कर 66% हो गया। कृषि परिवारों में से 71% ने अपनी वित्तीय बचत कर की।
- **किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी):** 44% कृषि परिवारों के पास किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) है।
- **बीमा कवरेज:** कम से कम एक बीमित सदस्य वाले परिवारों की संख्या 25.5% से बढ़कर 80.3% हो गई है। वाहन बीमा सबसे सामान्य प्रकार का बीमा है, जो 55% परिवारों को कवर करता है।
- **पेंशन कवरेज:** उन परिवारों का प्रतिशत, जिनके सदस्यों को किसी न किसी प्रकार की पेंशन प्राप्त होती है, 18.9% से बढ़कर 23.5% हो गया है। 60 वर्ष से अधिक आयु के सदस्यों वाले परिवारों में से 54% को पेंशन मिलती है।
- **वित्तीय साक्षरता:** वित्तीय साक्षरता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जहां 51.3% लोगों ने अच्छी वित्तीय समझ प्रदर्शित की है, जो कि पहले 33.9% थी। इसके साथ ही वित्तीय व्यवहार भी 56.4% से बढ़कर 72.8% हो गया है।

नाबार्ड के बारे में:

- राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। नाबार्ड ग्रामीण विकास को सुदृढ़ बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

	Agricultural Households	Non-Agricultural Households	All Households
All Sources Combined	13,661 (100)	11,438 (100)	12,698 (100)
Cultivation	4,476 (33)	-39 (0)	2,521 (20)
Livestock Rearing	1,677 (12)	-8 (0)	947 (7)
Other Enterprises	2,010 (15)	1,809 (16)	1,923 (15)
Wage Labour	2,238 (16)	2,927 (26)	2,536 (20)
Govt./ Pvt. Service	3,150 (23)	6,599 (57)	4,643 (37)
Other Sources	110 (1)	150 (1)	127 (1)

नाबार्ड के कार्य:

- **पुनर्वित्त सहायता:** ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पुनर्वित्त सहायता प्रदान करना।
- **ऋण योजना:** ग्रामीण वित्तपोषण लक्ष्यों की प्राप्ति में बैंकों को मार्गदर्शन और प्रेरित करने के लिए जिला स्तरीय ऋण योजनाओं का निर्माण करना।
- **विकास योजना का डिजाइन:** केंद्र सरकार के लिए विकास योजनाओं के डिजाइन और कार्यान्वयन में शामिल होना।
- **कारीगरों के लिए प्रशिक्षण और सहायता:** हस्तशिल्प कारीगरों को प्रशिक्षण प्रदान करना और उनके उत्पादों के विपणन के लिए मंच विकसित करना।
- **अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियां:** ग्रामीण विकास और कृषि अनुकूलन के लिए वैश्विक संगठनों और विश्व बैंक से संबद्ध संस्थानों के साथ सहयोग करना।
- **सहकारी और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पर्यवेक्षण:** सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) का पर्यवेक्षण करना और उन्हें बैंकिंग पद्धतियां विकसित करने में सहायता प्रदान करना।

बायोपॉलिमर के लिए भारत की पहली प्रदर्शन सुविधा का उद्घाटन

संदर्भ: हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने पुणे के जेजुरी में बायोपॉलिमर्स के लिए भारत की पहली प्रदर्शन सुविधा का उद्घाटन किया। प्राज इंडस्ट्रीज द्वारा निर्मित यह सुविधा भारत को जैव अर्थव्यवस्था और टिकाऊ प्रथाओं में वैश्विक नेतृत्व करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

- यह सुविधा पॉलीलैक्टिक एसिड (पीएलए) बायोप्लास्टिक के उत्पादन

Face to Face Centres
DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029
dhyeyaias.com

पर ध्यान केंद्रित करती है, जोकि पारंपरिक जीवाश्म-आधारित प्लास्टिक के लिए एक पर्यावरण-अनुकूल विकल्प प्रस्तुत करती है। इससे वैश्विक प्लास्टिक प्रदूषण संकट का समाधान संभव हो सकता है।

- यह सुविधा इस बात का उदाहरण है कि बायोप्लास्टिक में तकनीकी प्रगति किस तरह आर्थिक विकास और स्थिरता को बढ़ावा दे सकती है। इस पहल के माध्यम से भारत की पारंपरिक प्लास्टिक से टिकाऊ समाधानों की ओर संक्रमण की प्रतिबद्धता स्पष्ट होती है, जोकि सरकार की विभिन्न योजनाओं के लक्ष्यों के साथ मेल खाती है।

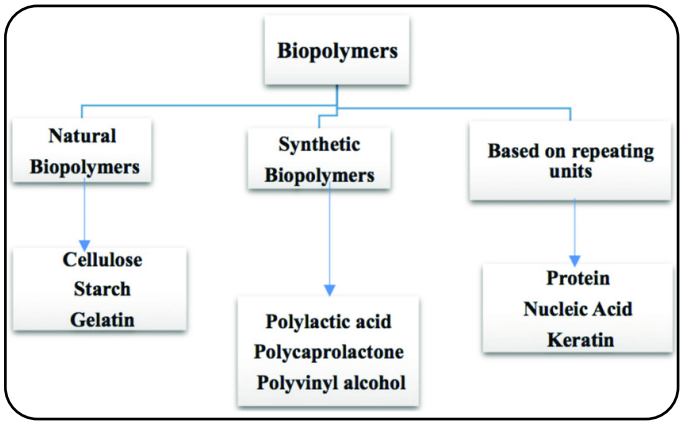

भारत में जैव प्रौद्योगिकी की वर्तमान स्थिति:

- भारत वैश्विक स्तर पर शीर्ष 12 जैव प्रौद्योगिकी गंतव्यों में से एक है, जहाँ कोविड-19 महामारी के बाद जैव प्रौद्योगिकी का क्षेत्र तेजी से विकसित हुआ है। देश ने वैक्सीन बनाने, नैदानिक परीक्षण करने और चिकित्सा उपकरणों में महत्वपूर्ण प्रगति की है।
- **बायोटेक स्टार्टअप:** 2021 में, भारत में रिकॉर्ड 1,128 बायोटेक स्टार्टअप पंजीकरण हुए, जो 2015 के बाद सबसे अधिक है। 2022 तक, बायोटेक स्टार्टअप की कुल संख्या 6,756 तक पहुंच गई, जिसके 2025 तक 10,000 तक पहुंचने की उम्मीद है।
- **जैव अर्थव्यवस्था में वृद्धि:** भारत की जैव अर्थव्यवस्था 2014 में 10 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2024 में 130 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गई है। यह अनुमान है कि यह 2030 तक 300 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँच जाएगी। बायोफार्मा क्षेत्र जैव अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा हिस्सा है, जो इसके कुल मूल्य का 49% है, लगभग 39.4 अरब अमेरिकी डॉलर। इसके अतिरिक्त, टीकाकरण बाजार का आकार 2025 तक 252 अरब रुपये (लगभग 3.04 अरब अमेरिकी डॉलर) तक पहुँचने की उम्मीद है।
- **जैव संसाधन:** भारत की विशाल जैव विविधता, विशेष रूप से हिमालय और इसकी 7,500 किलोमीटर लंबी तटरेखा, जैव प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करती है। इसका लाभ उठाने के लिए शुरू किये गये गहरे समुद्र मिशन का उद्देश्य समुद्र के नीचे जैव विविधता का पता लगाना और उसका दोहन करना है, जिससे इस क्षेत्र में भारत की क्षमता बढ़ सकेगी।

बायोई3 नीति: सतत विकास के लिए उत्प्रेरक

बायोई3 (E3) नीति (अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी) एक महत्वपूर्ण सरकारी पहल है जिसे विभिन्न क्षेत्रों में टिकाऊ जैव विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें उच्च-मूल्य वाले जैव-आधारित रसायन, बायोपॉलिमर, सटीक जैव चिकित्सा और जलवायु-लचीली कृषि शामिल हैं। इसके उद्देश्यों में शामिल हैं:

- **आर्थिक विकास:** 2030 तक भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 5-6% का योगदान करने का लक्ष्य रखते हुए, नीति का उद्देश्य 24 ट्रिलियन (लगभग 300 बिलियन डॉलर) मूल्य की जैव अर्थव्यवस्था स्थापित करना है।
- **रोजगार सृजन:** जैव विनिर्माण केंद्रों और जैव-एआई केंद्रों की स्थापना से विशेष रूप से टियर-II और टियर-III शहरों में बड़ी मात्रा में रोजगार अवसर पैदा होने की उम्मीद है।
- **स्थिरता:** जैव ईंधन आधारित समाधानों में परिवर्तन का समर्थन करके, यह नीति भारत के शुद्ध-शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य के अनुरूप है।
- **नवाचार और सहयोग:** यह नीति जैव प्रौद्योगिकी में अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करती है और नवीन समाधानों के व्यावसायीकरण में तेजी लाने के लिए उद्योग, शिक्षा और सरकार के बीच सहयोग को बढ़ावा देती है।

प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना

संदर्भ: हाल ही में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य उभरते रोजगार बाजार के लिए भारतीय युवाओं को आवश्यक कौशल प्रदान करना है।

- यह पहल कौशल विकास और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने की सरकार की व्यापक रणनीति का हिस्सा है, जिसका लक्ष्य अगले पांच वर्षों में एक करोड़ युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना है।

योजना की मुख्य विशेषताएं

- 2024-25 के केंद्रीय बजट में घोषित इस योजना की शुरुआत एक पायलट परियोजना के रूप में हुई है, जोकि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 1.25 लाख इंटर्नशिप को लक्षित करती है। इसमें तेल, गैस, ऊर्जा, यात्रा, आतिथ्य, ऑटोमोटिव, और बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाएं सहित कुल 24 क्षेत्र शामिल हैं।
- इस पायलट प्रोजेक्ट के लिए चुनी गई कंपनियों का चयन पिछले तीन वर्षों के दौरान उनके कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) व्यय के आधार पर किया गया है। यह सुनिश्चित किया गया है कि प्रतिभागियों को ऐसे संगठनों में रखा जाए, जो नैतिक प्रथाओं के लिए प्रतिबद्ध हैं।

- यह योजना सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मौजूदा कौशल विकास कार्यक्रमों, प्रशिक्षुता और छात्र प्रशिक्षण पहलों से स्वतंत्र है। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना का प्रमुख ध्यान इंटर्नशिप पर है, जिसका उद्देश्य युवाओं को एक ऐसा मूल्यवान अनुभव प्रदान करना है जो उनकी रोजगार क्षमता को सुदृढ़ करता है। यह कार्यक्रम प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवाओं को भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करेगा।

वित्तीय सहायता:

- प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के अंतर्गत प्रशिक्षुओं को उनकी इंटर्नशिप अवधि के दौरान 5,000 रुपये का मासिक वजीफा प्राप्त होगा, जिसकी संरचना निम्नलिखित है:

योगदान का विवरण:

- उपस्थिति और आचरण के आधार पर साझेदार कंपनियों द्वारा 500 रूपए का योगदान किया जाएगा।
- शेष 4,500 रुपये सरकार द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से प्रशिक्षु के आधार से जुड़े बैंक खाते में प्रदान किए जाएंगे।

अतिरिक्त अनुदान:

- इंटर्नशिप में शामिल होने पर प्रशिक्षुओं को डीबीटी के माध्यम से 6,000 रुपये का एकमुश्त अनुदान भी मिलेगा।

बीमा कवरेज:

- सभी प्रशिक्षुओं को सरकार की बीमा योजना के अंतर्गत कवर किया जाएगा:
  - » प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना
  - » प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना
- सरकार इन बीमा पॉलिसियों के प्रीमियम का भुगतान करेगी। साझेदार कंपनियाँ अपने प्रशिक्षुओं के लिए अतिरिक्त दुर्घटना बीमा कवरेज भी प्रदान कर सकती हैं।

पीएम इंटर्नशिप पोर्टल के माध्यम से कार्यान्वयन:

- यह योजना एक केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से संचालित होती है जो संपूर्ण इंटर्नशिप का प्रबंधन करती है। यह प्लेटफॉर्म योग्य उम्मीदवारों को रिज्यूमे बनाने, इंटर्नशिप ब्राउज करने और अपने पसंदीदा क्षेत्रों में पदों के लिए आवेदन करने की सुविधा प्रदान करता है। योजना में विविधता और सामाजिक समावेशिता पर विशेष जोर दिया गया है, जिससे हाशिए पर पड़े समुदायों का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होता है।

वायनाड में भूस्खलन की निगरानी के लिए एक्स-बैंड रडार

संदर्भ: हाल ही में केरल के वायनाड जिले में आई विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन में 200 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई। इसके प्रत्युत्तर में, केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने आपदा प्रबंधन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से इस क्षेत्र में एक्स-बैंड रडार की स्थापना को स्वीकृति दी है।

- मूसलाधार वर्षा के कारण पुंचिरिमट्टम के निकट गंभीर भूस्खलन हुआ, जिससे भारी मात्रा में मलबा बहकर तबाही का कारण बना।

रडार प्रौद्योगिकी:

- **रडार:** रडार का पूरा अर्थ 'रेडियो डिटेक्शन और रेंजिंग' है। यह वस्तुओं का पता लगाने और उनकी दूरी, वेग, तथा अन्य विशेषताओं को मापने के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग करता है। इसमें एक ट्रांसमीटर द्वारा लक्षित वस्तु (जैसे बादल) पर एक संकेत भेजा जाता है, जो लक्षित वस्तु से टकराकर परावर्तित होता है और रिसीवर के पास वापस आता है, जहां उसका विश्लेषण किया जाता है।
- **डॉप्लर प्रभाव:** यह सिद्धांत बताता है कि जब कोई स्रोत पर्यवेक्षक के सापेक्ष गति करता है, तो तरंगों की आवृत्ति बदल जाती है। यह परिवर्तन रडार को बादलों की गति, दिशा और वेग का सटीक पता लगाने में मदद करता है।

एक्स-बैंड रडार:

- एक्स-बैंड रडार 8-12 गीगाहर्ट्ज रेंज में 2-4 सेमी की तरंग दैर्ध्य का उपयोग करता है। इसकी मदद से बारिश की बूंदों और कोहरे जैसे छोटे कणों का पता लगाकर उच्च-रिजॉल्यूशन इमेजिंग बनाई जा सकती है। हालांकि, इसकी उच्च आवृत्ति की वजह से सिग्नल जल्दी कमजोर हो जाता है, जिससे इसकी परिचालन सीमा कम हो जाती है।
- वायनाड क्षेत्र में इसका उपयोग मिट्टी की गतिविधियों की निगरानी के लिए किया जाएगा, जिससे भूस्खलन की सटीक भविष्यवाणी करने में मदद मिलेगी। इसकी तेजी से डेटा इकट्ठा करने की क्षमता पर्यावरणीय

बदलावों को तुरंत ट्रैक करने में सहायक होगी।

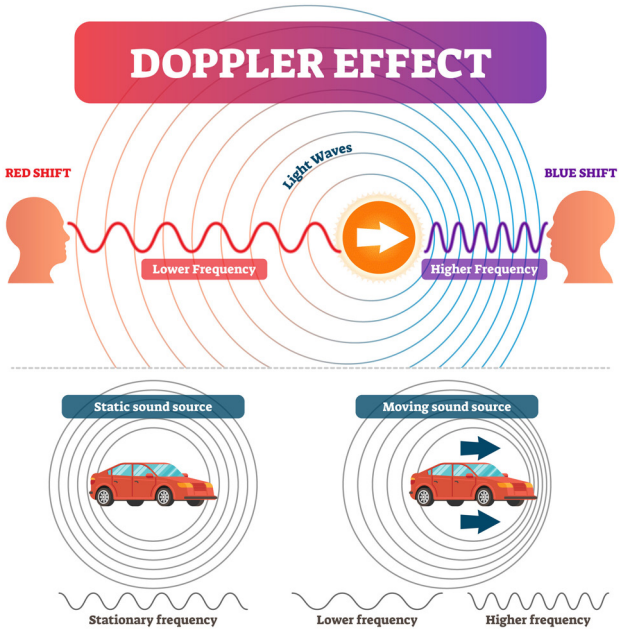

भारत का मौसम विज्ञान रडार नेटवर्क:

- भारत में मौसम रडार की तैनाती 1950 के दशक में शुरू हुई थी। पहला स्वदेशी एक्स-बैंड रडार 1970 में नई दिल्ली में स्थापित किया गया था।

वर्तमान क्षमताएं:

- वर्तमान में, देश में विभिन्न मौसमीय अनुप्रयोगों के लिए एक्स-बैंड और एस-बैंड रडार का उपयोग किया जा रहा है। 2-4 गीगाहर्ट्ज पर संचालित एस-बैंड रडार का उपयोग मुख्यत: लंबी दूरी की पहचान के लिए किया जाता है। इस श्रेणी का पहला रडार 1970 में विशाखापत्तनम में स्थापित किया गया था।

भविष्य के विकास:

- सरकार ने 2,000 करोड़ रुपये के 'मिशन मौसम' के तहत 2026 तक 60 नए मौसम संबंधी रडार स्थापित करने की योजना बनाई है, जिसमें 56 डॉप्लर रडार शामिल हैं।
- पूर्वोत्तर राज्यों और हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिलों में बेहतर मौसम पूर्वानुमान के लिए 10 नए एक्स-बैंड डॉप्लर रडार खरीदे जा रहे हैं।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग: निसार परियोजना

- नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से 'निसार' (NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar) परियोजना शुरू की गई है, जिसमें रडार इमेजिंग के जरिए पृथ्वी की भू-आकृतियों के उच्च-रिजॉल्यूशन मानचित्र बनाए जाएंगे।
- **घटक:** इस उपग्रह में नासा का एल-बैंड रडार (1.25 गीगाहर्ट्ज, 24 सेमी) और इसरो का एस-बैंड रडार (3.2 गीगाहर्ट्ज, 9.3 सेमी) शामिल होगा, जोकि प्राकृतिक परिवर्तनों पर नजर रखेगा।
- **प्रक्षेपण योजना:** 2025 में इसरो के जीएसएलवी एमके II रॉकेट से इसका प्रक्षेपण किया जाएगा। इस परियोजना की कुल लागत 1.5 बिलियन डॉलर है, जिसका मुख्य वित्तपोषण नासा द्वारा किया जाएगा।

पॉवर पैक्ड न्यूज

इंडो-यूएस एंडोमेंट अवार्ड्स

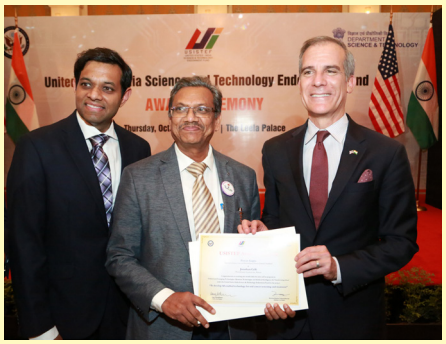

- हाल ही में 12 अक्टूबर, 2024 को केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने 17 सहयोगी टीमों को इंडो-यूएस एंडोमेंट अवार्ड्स प्रदान किए। ये टीमें यू.एस.- इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंडोमेंट फंड (USISTEF) का हिस्सा हैं, जोकि एआई-सक्षम तकनीकों और क्वांटम संचार को आगे बढ़ाने पर केंद्रित हैं।
- दोनों सरकारों ने नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को प्रोत्साहित करने के लिए महत्वपूर्ण समझौते किए हैं। भारत ने सेमीकंडक्टर क्षेत्र के लिए डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव (DLI) और ऑटोमोबाइल तथा ड्रोन जैसे क्षेत्रों के लिए उत्पादन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजनाओं को लागू करके सुधारात्मक कदम उठाए हैं।
- डॉ. सिंह ने भारत के विकसित होते स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रकाश डाला, जो 2014 में 350 स्टार्ट-अप से बढ़कर अब 1,40,000 से अधिक हो गया है, जिसमें 110 यूनिकॉर्न शामिल हैं।
- यह पहल भारत-अमेरिका संबंधों को मजबूत करती है और दोनों देशों को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों में अग्रणी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

ध्येय IAS
most trusted since 2003

DAILY prePARE
Current affairs summary for prelims

15 October 2024

ड्रैगन ड्रोन

- रूस-यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष में, 'ड्रैगन ड्रोन' नामक एक नया घातक हथियार सामने आया है, जो थर्माइट नामक पिघले हुए पदार्थ को छोड़ने में सक्षम है।
- थर्माइट यह एल्युमिनियम और आयरन ऑक्साइड का एक संयोजन है, जो 2,427 डिग्री सेल्सियस के अत्यधिक तापमान पर जलता है और इसे बुझाना मुश्किल होता है। यह एक शक्तिशाली अग्निज्वलक के रूप में कार्य करता है। यह विभिन्न सामग्रियों में प्रवेश कर गंभीर जलन और सैन्य उपकरणों तथा कर्मियों को व्यापक नुकसान पंहुचा सकता है।

- प्रारंभ में, यूक्रेनी सेनाओं ने इन ड्रोन का इस्तेमाल करके रूसी सेना के ठिकानों को निशाना बनाया।
- बाद में, रूस की सेना ने भी इन ड्रनों का उपयोग करना शुरू कर दिया।
- थर्माइट का युद्ध में ऐतिहासिक उपयोग रहा है, जिसमें दोनों विश्व युद्धों में इसके उपयोग शामिल हैं। हालांकि, आधुनिक संघर्ष में इसका उपयोग महत्वपूर्ण नैतिक चिंताओं को जन्म देता है।
- अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत थर्माइट का उपयोग स्पष्ट तौर पर प्रतिबंधित नहीं है, लेकिन नागरिक लक्ष्यों के खिलाफ इसके इस्तेमाल पर कुछ पारंपरिक हथियारों के कन्वेंशन द्वारा रोक लगाई गई है। यह इस बात को दर्शाता है कि थर्माइट का उपयोग किया जा सकता है और इससे गंभीर नुकसान हो सकता है